

Statement-II

Details of tentative target of bore holes to be drilled by CGWB in Gujarat during 1998-99.

Sl. No.	Name of Districts	No. of bore holes
1.	Sabarkantha, Banaskantha and Gandhi Nagar	8
2.	Kutch and Coastal Saurashtra	20
3.	Bharuch, Baroda and Surat	10
4.	Junagarh	32
5.	Mehsana and Ahmedabad	9
TOTAL		79

Fund Allocated for Irrigation Projects in Gujarat

616. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of funds allocated to the State of Gujarat by the Central Government for undertaking irrigation projects during the last three years, year-wise;

(b) whether the sanctioned funds have been utilized by the State during the period; and

(c) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (c) The details of funds allocated to Gujarat and its utilisation during the last three years is as under:

(Rs. in crores)

	Actual Outlay	Actual Expenditure/ Revised Outlay
1995-96	649.23	(actual) 785.93
1996-97	1232.88	(Revised) 1232.88
1997-98	1374.00	(Revised) 1374.00

देश में सिंचाई परियोजनाएं

617. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय मंत्री द्वारा पदभार संभालने के बाद राज्यों द्वारा उनके मंत्रालय को अनुमोदन के लिये कई सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तुत की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार गुजरात समेत राज्य-वार लम्बित परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ग) अब तक उनमें से अनुमोदित की गई सिंचाई परियोजनाओं का गुजरात समेत राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितनी सिंचाई परियोजनाओं के लिए तकनीकी सलाह मांगी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) :

(क) जी, हां। मार्च, 1998 तक 9 वृहद और 5 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) लंबित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा विवरण - I में (नीचे देखिये) दिया गया है।

(ग) और (घ) तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्राप्त 148 सिंचाई परियोजनाओं में से गुजरात राज्य ने 12 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को अंतर्राज्यीय पहलुओं में शामिल न होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए हैं और 10 और परियोजनाएं तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण II (नीचे देखिये) में दिया गया है।

विवरण – I

राज्य का नाम	वृहद	मध्यम	कुल
आन्ध्र प्रदेश	8	2	10
असम	1	2	3
बिहार	7	1	8
गुजरात	1	1	2
हरियाणा	5	2	7
हिमाचल प्रदेश	1	2	3
जम्मू व कश्मीर	-	16	16
कर्नाटक	4	1	5
केरल	2	1	3
मध्य प्रदेश	9	-	9
महाराष्ट्र	15	24	39
मणिपुर	1	1	2

राज्य का नाम	वृहद	मध्यम	कुल
मेघालय	-	-	-
नागालैंड	-	1	1
उड़ीसा	6	6	12
पंजाब	3	1	4
राजस्थान	5	5	10
सिक्किम	-	-	-
तमिलनाडु	1	1	2
त्रिपुरा	-	-	-
उत्तर प्रदेश	11	-	11
पश्चिम बंगाल	1	-	1
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
गोवा, दमन व दीव	-	-	-
कुल योग	81	67	148

विवरण – II

क्र० सं०	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	अनुमानित लाभ हैक्टयर लागत में (करोड़ रु० में)		स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	चांगलनाडु लिफ्ट सिंचाई	आंध्र प्रदेश	43.05	10,118	तकनीकी
2.	प्रियदर्शिनी जुराला परियोजना (वृहद)	आंध्र प्रदेश	545.82	87,835	सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत
3.	बरीसूती सिंचाई परियोजना (मध्यम)	असम	34.70	11,500	
4.	बाल्ह घाटी सिंचाई परियोजना (मध्यम)	हिमाचल प्रदेश	12.02	3,037	
5.	तालाम्बा सिंचाई परियोजना (वृहद)	महाराष्ट्र	289.09	28,900	
6.	कार सिंचाई परियोजना (मध्यम)	महाराष्ट्र	44.71	6,359	

1	2	3	4	5	6
7.	डससूजा सिंचाई परियोजना (मध्यम)	नागालैंड	49.00	11,500	
8.	रेंगाली सिंचाई उप परियोजना (दाया तट नहर) (वृहद)	उड़ीसा	738.27	1,70.850	
9.	धीरगोथ सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	16.80	3,010	
10.	हिण्डेन कृष्णी दोआब में खरीफ चैनल प्रदान करना (वृहद)	उत्तर प्रदेश	39.24	11,600	
11.	ओजात-II (मध्यम)	गुजरात	59.70	7,520	अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल न होने के संबंध में प्रमाण-पत्र जारी किये गये।
12.	उन्द - II	-वही-	38.94	4,250	
13.	वारतृ-II (मध्यम)	-वही-	30.40	6,151	
14.	लिम्बदी भोगावो - II	-वही-	34.88	3,605	
15.	सानी (संशोधित) (-वही-)	-वही-	12.57	2,759	
16.	अमीपुर (संशोधित) (मध्यम)	-वही-	3.00	6.775	
17.	मिट्टी (-वही-)	-वही-	14.50	2,025	
18.	अजी- II (-वही-)	-वही-	75.16	3,833	
19.	भादेर - II (-वही-)	-वही-	73.10	9,495	
20.	सुरवों (-वही-)	-वही-	27.50	2,777	
21.	डेमी- III (-वही-)	-वही-	28.00	2,605	
22.	फुलजोर (-वही-)	-वही-	23.50	2,319	

1

Financial Assistance to flood affected States

618. SHRI KARNENDU BHATTACHAJEE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of measures taken and financial assistance extended to Bihar, West Bengal and Assam and Andhra Pradesh to fight the flood menace during the period from June to November, 1998;

(b) the estimated loss of life and property reported from these States;

(c) the amount of financial assistance

asked for by these States and the financial assistance provided to them by the Central Government; and

(d) what steps on permanent footing like raising of banks of rivers, deepening the rivers or construction of bunds Government propose to take to curb these recurring floods in these States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL). (a) Primarily; it is the responsibility of State Government concerned to undertake necessary relief and